



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052025-262895
CG-DL-E-05052025-262895

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1946]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 2025/ वैशाख 12, 1947

No. 1946]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 2025/ VAISAKHA 12, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2025

का.आ. 1990(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1701(अ), तारीख 26 मई, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1701(अ), तारीख 26 मई, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग

II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1701(अ), तारीख 26 मई, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

“5. निगरानी समिति. – केंद्रीय सरकार निगरानी समिति के नाम से ज्ञात एक समिती का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

- | | | |
|------|--|---------------------|
| (1) | क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर | - अध्यक्ष, पदेन; |
| (2) | विधान सभा के सदस्य, विराजपेट निर्वाचन क्षेत्र, कोडागु जिला | - सदस्य, पदेन; |
| (3) | पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (4) | कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (5) | क्षेत्रीय अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर | - सदस्य, पदेन; |
| (6) | उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि, कोडागु जिला, मडिकेरी | - सदस्य, पदेन; |
| (7) | कर्नाटक राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ जो हर तीन वर्ष के लिए समय-समय पर कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। | - सदस्य; |
| (8) | पर्यावरण या वन्य जीवन या विरासत संरक्षण सहित प्राकृतिक संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो हर तीन वर्ष के लिए समय-समय पर कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। | - सदस्य; |
| (9) | राज्य जैव विविधता बोर्ड, कर्नाटक के सदस्य सचिव या सदस्य | - सदस्य, पदेन; |
| (10) | उप वन संरक्षक, मडिकेरी वन्यजीव प्रभाग, मडिकेरी | - सदस्य सचिव, पदेन। |

***(कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, यदि आवश्यक हो तो कर्नाटक विधान सभा के अध्यक्ष से अनुमति सहित प्रासंगिक अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन)।**

6. निगरानी समिति के कार्य.- (1) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में सम्मिलित हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनुमति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या उप आयुक्त या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

- (4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी।
- (5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-V में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करेगी।
- (6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकेगी, जैसा वह उचित समझे।”

[फा.सं.25/168/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक “जी”

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में का.आ. 1701(अ), तारीख 26 मई, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2025

S.O. 1990(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an eco-sensitive Zone around Brahmagiri Wildlife Sanctuary, Karnataka *vide* S.O. 1701(E), dated the 26th May, 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1701(E), dated the 26th May, 2017;

NOW THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change, *vide* S.O. 1701(E), dated the 26th May, 2017 namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely:-

“5. **Monitoring Committee.** — The Central Government hereby constitutes a Committee to be known as Monitoring Committee, which shall comprise of the following persons, namely: -

- | | |
|--|--|
| (1) The Regional Commissioner, Mysuru | Chairman, <i>ex officio</i> ; |
| (2) Member of Legislative Assembly, Virajpet Constituency, Kodagu District | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (3) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (4) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (5) The Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysuru | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (6) Deputy Commissioner or his representative, Kodagu District, Madikeri | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (7) One expert in ecology from reputed institution or university of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka from time to time every three years | Member; |
| (8) One representative of a non-governmental organisation working in the field of environment or wildlife or natural conservation including heritage conservation to be nominated by the Government of Karnataka from time to time every three years | Member; |
| (9) Member Secretary or Member of the State Biodiversity Board, Karnataka | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (10) The Deputy Conservator of Forests, Madikeri Wildlife Division, Madikeri | Member Secretary,
<i>ex officio</i> . |

*(Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required).

6. **Functions of Monitoring Committee.**— (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

- (3) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the concerned Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.
- (5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in proforma specified in Annexure-V.
- (6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”.

[F. No. 25/168/2015-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1701(E), dated the 26th May, 2017.